

## उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति- 2023

### चर्चा में क्यों?

13 मार्च, 2023 को मीडिया से मली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड के चमोली ज़िले में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति (उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति- 2023) को मंजूरी दी गई।

### प्रमुख बिंदु

- उत्तराखण्ड राज्य सौर ऊर्जा नीति- 2023 में सरकार ने यह अपेक्षा जताई है कि दिसंबर 2027 तक प्रदेश में 2500 मेगावाट बजिली का उत्पादन इस प्रोजेक्ट से होगा। इनसे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीणों की आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे।
- नई सौर ऊर्जा नीति के तहत नज़ी उपयोग या तीसरे पक्ष की बिक्री के लिये सरकारी या नज़ी भूमि पर भी सौर ऊर्जा की परियोजनाएँ लगाई जा सकेंगी।
- यूपीसीएल के स्तर से राज्य के बाहर भी सौर ऊर्जा की परियोजनाएँ लगाई जा सकेंगी। यह प्रावधान इसलिये किया गया है क्योंकि यूपीसीएल को अपनी खरीदी जाने वाली बजिली का एक नश्चिति प्रतशित सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट से खरीदना अनविर्य है।
- नई पॉलिसी में स्थानीय युवाओं के लिये रोज़गार की भी गारंटी दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो भी सरकारी भूमि को लीज पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा, उसे 70 प्रतशित स्थानीय युवाओं को रोज़गार देना होगा। उरेडा अपने टेंडर में इस शर्त को जारी करेगा।
- पॉलिसी में यह प्रावधान भी किया गया है कि यूपीसीएल सौर ऊर्जा का एक ग्रीन टैरफि प्रस्ताव तैयार करेगा, जो कि नियामक आयोग को भेजा जाएगा। नियामक आयोग उपभोक्ताओं के लिये ग्रीन टैरफि चुनने का विकल्प दे सकता है।
- इसके अलावा पीक आवर्स में ग्रडि में सौर ऊर्जा देने वालों को फीड इन टैरफि से प्रोत्साहित कर सकता है। आसान पहुँच व नगिरानी के लिये वर्चुअल नेट मीटरिंग (वीएनएम) और ग्रुप नेट मीटरिंग (जीएनएम) का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- नई पॉलिसी में उरेडा की ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ाई गई हैं। इसके तहत उरेडा को एक सोलर पॉलिसी सेल की स्थापना करनी होगी, जिसके तहत सगिल वडि के माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट को पास किया जाएगा। उरेडा को लैंडबैंक बनाना होगा तथा सभी सरकारी ज़मीनें और भवनों की सूची बनानी होगी, जहाँ सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लग सकते हैं। इसी प्रकार, ऐसी नज़ी भूमि भी चनिहता करनी होंगी, जनि पर कोई प्राइवेट व्यक्ती लीज पर अपना प्रोजेक्ट लगा सके।
- नई नीति से मलने वाले फायदे-
  - सगिल वडि पोर्टल के माध्यम से सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगेंगे।
  - लैंड यूज परविरतन शुल्क, न्यायालय शुल्क, पंजीकरण, भूमि उपयोग अनुमोदन, बाहरी विकास शुल्क, जाँच शुल्क और बुनयादी ढाँचा विकास शुल्क में छूट मलिंगी।
  - जो भी प्रोजेक्ट लगेगा, यूपीसीएल को अनविर्य तौर पर उससे बजिली खरीदनी होगी। इससे नविशकों का जोखमि कम होगा।
  - फीड इन टैरफि के माध्यम से अतरिकित बजिली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं को मुआवज़ा मलिंगा। वहीं, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास एवं स्वरोज़गार योजना को भी इससे लाभ पहुँचेगा।
  - अपने उपयोग के लिये और सामूहिक उपयोग के लिये नरिबाध अभगिम और एसजीएसटी व बजिली शुल्क में छूट मलिंगी।